

44 भाजपा कार्यकर्ता संभालेंगे जिला में सेवा संकल्प अभियान की बागडोर

राष्ट्रसेवा का महासंकल्प, 25 वर्षों की गौरवगाथा लेकर घर-घर जाएंगे कार्यकर्ता , हर कार्यकर्ता अपने बूथ एवं प्रवासी बूथ पर जन-जन तक पहुंचायेगे मोदी जी के 25 वर्षों की सेवा यात्रा

समय जगत, झांसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत भाजपा कार्यालय में बैठक का विधिवत शुभारंभ उपस्थित अतिथियों एवं पदाधिकारियों द्वारा महापुरवों के चित्रों पर पुष्पजलि, माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह, जिला महामंत्री अरविंद राजपूत ,विनोद नायक , जिला उपाध्यक्ष अभिषेक जैन,जिला मंत्री मीनू राजावत, जिला महामंत्री युवा मोर्चा मुकुल द्विवेदी उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प एवं सेवा को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 2026 आयोजित किया जा रहा है।

कार्यशाला की प्रस्तावना जिला महामंत्री अरविंद राजपूत ने रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 'सेवा संकल्प अभियान' के उद्देश्य, रूपरेखा एवं आगामी कार्यक्रमों के जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, जनकल्याण, सुशासन और अंत्योदय के प्रति समर्पण की प्रेरणादायी यात्रा है।

जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह के द्वारा सेवा संकल्प अभियान जिला अभियान समिति में कार्यक्रमवार कार्य विभाजन निम्न प्रकार से किया आशीर्वाद का दीया (17 सितम्बर)रूजनप्रतिनिधि श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त),



संयोजक श्री हेमंत खंगार (नि मण्डल अध्यक्ष), सहसंयोजक श्री रवि राजपूत (जिला महामंत्री युवा मोर्चा) मेरे सपनों का भारत - चित्र सेवा (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर)

जनप्रतिनिधि श्री पवन गौतम (जिला पंचायत अध्यक्ष), संयोजक श्री अनिरुद्ध दुबे (जिला मंत्री), स हसंयोजक श्री अंकित साहू (जिला सहकोषाध्यक्ष), श्री मोहित पोरवाल (जिला सहमीडिया प्रभारी), श्री शुभम बनर्जी (पूर्व जिला मंत्री युवा मोर्चा), श्री राहुल कुर्मी (जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा)।नमो सेवा - अनकही कहानियाँ (18 सितम्बर से 15 अक्टूबर)जनप्रतिनिधि श्रीमती रमा निरंजन (एम.एल.सी.), संयोजक श्री बंटी सोनी (सभासद), सहसंयोजक श्रीमती संगीता जोशी (सक्रिय कार्यकर्ता)।आँगन मिलना सेवा (25 सितम्बर से 2 अक्टूबर)

जनप्रतिनिधि श्री अनुराग शर्मा (सांसद), संयोजक श्रीमती सीमा शर्मा (जिला कार्यकारिणी सदस्य), सहसंयोजक श्री पंकज दुबे

(डायेरेक्टर अरबन बैंक)।सेवा की कहानी (17 सितम्बर से 17 अक्टूबर) संयोजक श्री रानू देवलिया (जिला उपाध्यक्ष), सहसंयोजक श्री सिद्धेश होगी) जनप्रतिनिधि श्री जयदेव पुरोहित (चेयरमेन जिला सहकारी बैंक), संयोजक श्री विनोद नायक (जिला महामंत्री), सहसंयोजक श्री अशोक कुशवाहा (उपसभासद डी.सी.डी.एफ)।का संक्षिप्त विवरण बताया एवं अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का जीवन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर सेवा, संगठन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कृतित्व से प्सेवाष् शब्द के मूल भाव को जन-जन तक पहुंचाया है और उसे शासन की संस्कृति बनाया है।प्रधानमंत्री जी के जीवन का उद्देश्य अंत्योदय, राष्ट्र प्रथम का भाव और सुशासन रहा है। यह त्रिवेणी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल

सेवा सेतु अभियान (8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर)रूजनप्रतिनिधि श्री रामतीर्थ सिंघल (एम.एल.सी.), संयोजक श्री आदेश गुप्ता (मनोनीत सभासद), सहसंयोजक श्री धर्म कोरसिया (मनोनीत सभासद)। सेवा रां राष्ट्र के संग (7 अक्टूबर) रूजनप्रतिनिधि श्री राजीव सिंह पारीछ (विधायक), संयोजक श्री मनमोहन गंडा (क्षेत्रीय सहसंयोजक व्यापार प्रकोष्ठ), सहसंयोजक श्री रोहित गोठनकर (नि. जिला मंत्री)।

बडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा (तिथि केन्द्र द्वारा निर्धारित)

जनप्रतिनिधि श्री राजकानेश वर्मा (ब्लॉक प्रमुख चिरावाँ), संयोजक श्री रानू देवलिया (जिला उपाध्यक्ष), सहसंयोजक श्री सिद्धेश होगी) जनप्रतिनिधि श्री जयदेव पुरोहित (चेयरमेन जिला सहकारी बैंक), संयोजक श्री विनोद नायक (जिला महामंत्री), सहसंयोजक श्री अशोक कुशवाहा (उपसभासद डी.सी.डी.एफ)।का संक्षिप्त विवरण बताया एवं अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का जीवन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर सेवा, संगठन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कृतित्व से प्सेवाष् शब्द के मूल भाव को जन-जन तक पहुंचाया है और उसे शासन की संस्कृति बनाया है।प्रधानमंत्री जी के जीवन का उद्देश्य अंत्योदय, राष्ट्र प्रथम का भाव और सुशासन रहा है। यह त्रिवेणी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल

सेवा सेतु अभियान (8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर)रूजनप्रतिनिधि श्री रामतीर्थ सिंघल (एम.एल.सी.), संयोजक श्री आदेश गुप्ता (मनोनीत सभासद), सहसंयोजक श्री धर्म कोरसिया (मनोनीत सभासद)। सेवा रां राष्ट्र के संग (7 अक्टूबर) रूजनप्रतिनिधि श्री सुशीला कुशवाहा (चेयरमेन नगर पालिका बर आसागर), संयोजक श्री अंकित राजा यादव (जिला मंत्री),

सहसंयोजक श्री विकास शर्मा (जिला सहसंयोजक विधि प्रकोष्ठ)।

सेवा फ़स्ट इनिवेशन चौलेंज (उत्तर प्रदेश हेतु प्रस्तावित नहीं है)जनप्रतिनिधि श्री वीरेंद्र प्रताप यादव (पूर्व जिला पंचायत सदस्य), संयोजक श्री चेतन ओझा (जिला संयोजक सोशल मीडिया), सहसंयोजक श्री हर्ष जैन (सक्रिय कार्यकर्ता / पूर्व प्रदेश सहमंत्री ए.बी.वी.पी.)।सुशासन सेवा संवाद (कार्ययोजना केन्द्र द्वारा प्रस्तावित होगी) जनप्रतिनिधि श्री जयदेव पुरोहित (चेयरमेन जिला सहकारी बैंक), संयोजक श्री विनोद नायक (जिला महामंत्री), सहसंयोजक श्री अशोक कुशवाहा (उपसभासद डी.सी.डी.एफ)।का संक्षिप्त विवरण बताया एवं अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का जीवन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर सेवा, संगठन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कृतित्व से प्सेवाष् शब्द के मूल भाव को जन-जन तक पहुंचाया है और उसे शासन की संस्कृति बनाया है।प्रधानमंत्री जी के जीवन का उद्देश्य अंत्योदय, राष्ट्र प्रथम का भाव और सुशासन रहा है। यह त्रिवेणी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल

उपाध्याय जी, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिए गए संस्कारों से निर्मित हुई है, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने अपने आचरण से जीवंत किया है।अधिकतम पहुँच, अधिकतम सहभागिता, अधिकतम सेवा और उसका प्रभावी क्रियान्वयन, अधिकतम धरातलीय गतिविधि, सोशल मीडिया का सक्रिय एवं सुनियोजित उपयोग, तथा प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्णता का स्वामित्व, अर्थात, प्रत्येक कार्यकर्ता केवल सहभागी नहीं, अपितु अपने दायित्व का उत्तरदायी सवाहक बने, यही इस अभियान का लक्ष्य है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सेवा संकल्प अभियान को केवल कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे जनसेवा और संगठन के विस्तार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। कार्यशाला में पदाधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव साझा किए तथा संगठन की विचारधारा एवं प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग तेज , बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

खनन से धरोहर बचाने और बुंदेलखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए अलग राज्य जरूरी: यज्ञेश कुमार गुप्ता

समय जगत, झांसी। पृथक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने आंदोलन को तेज करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से अनुरोध पत्र सौंपा। 11 सितंबर 2026 को जारी पत्रांक 103 के माध्यम से समिति ने बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, पर्यावरणीय संकट तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई।

समिति ने कहा कि बुंदेलखंड की अस्मिता, स्वाभिमान, भाषा, संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने के लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य का



निर्माण आवश्यक है। समिति ने प्रधानमंत्री से इस दिशा में निर्णायक पहल करते हुए लंबे समय से चली आ रही राज्य निर्माण की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

तीनों स्तरों पर भाजपा सरकार, समिति ने बताया अनुकूल समय ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान समय में उत्तर

प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रकृतीनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में समिति के अनुरोध पृथक बुंदेलखंड राज्य के गठन की दिशा में पहल के लिए यह अनुकूल अवसर है। समिति ने केंद्र सरकार से बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्माण की

प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

ज्ञापन पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञेश कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री ज्ञानेश्वर कुशवाहा सहित गोविंद दास, संजय आनंद, शिवम झा (केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य), लक्ष्मण प्रसाद, रमेश चंद्र, दीपक कुमार और पीयूष पयोधि पांडेय समेत अनेक पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर रहे।

बुंदेलखंड राज्य निर्माण का संकल्प दोहराया बुंदेलखंड की पहचान और प्राकृतिक संपदा बचानी है, तो बुंदेलखंड को अपना राज्य दिलाना होगा।+

झाँसी रेल मंडल परिक्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक आयोजित

समय जगत, झांसी। भारतीय रेल देश की जीवरेखा है और देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे भारतीय रेल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज दिनांक 11 सितम्बर 2026 को झाँसी के प्रतिष्ठित ओरछ पैलेस एवं कन्वेंशन सेंटर होटल ओरछ के सभागार में उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मण्डल के माननीय सांसदों एवं उनके सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक की एक उच्च स्तरीय एवं महत्वपूर्ण बैठक का माननीय सांसद झांसी ललितपुर



श्री अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मण्डल की हालिया उपलब्धियों को साझा करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की समीक्षा करना तथा माननीय जनप्रतिनिधियों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त कर रेल विकास योजनाओं को नई दिशा देना रहा।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह ने कहा कि, हमने अपनी रेलवे की कार्यप्रणाली में लाइन क्षमता की वृद्धि, यात्री सुविधाओं में सुधार एवं उन्नयन, गाड़ियों का संरक्षित संचालन, कर्मचारी कल्याण, पर्यावरण की संरक्षण के लिए हरित पहल की दिशा में विशेष कदम उठाए

हैं और इंफ्रस्ट्रक्चर के विकास और इसे मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है, रेल की विभिन्न परियोजनाएं जो वर्षों तक पर्याप्त फंड की अनुपलब्धता के कारण रुक जाते थे, उन कार्यों को करने हेतु सरकार द्वारा अब पर्याप्त

फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही उच्चतम स्तर से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होने से प्रोजेक्ट पूर्ण होने में तेजी आई है। साथ ही भारतीय रेल अपनी कार्यप्रणाली में इन्वेंशन और आधुनिक तकनीक का कारगर प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने सम्मानित यात्रियों, रेल उपयोगकर्ताओं और आमजन की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, इस हेतु एआई आधारित रेल मदद पोर्टल (139) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

निलंबित महामंत्री रूपम पाण्डेय 5 वर्ष के लिए निष्कासित, नए महामंत्री बने कुंदन कुमार सिंह

समय जगत, झांसी। आज उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की जोनाल कार्य समिति बैठक प्रयागराज में केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार विश्वकर्मा जी की अध्यक्षता में संसप्त हुई जिसमें 20 कार्य समिति सदस्यों में से 16 कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं रेलवे उद्योग प्रभारी श्रीमान अशोक कुमार शुकला जी, प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार उपाध्याय जी, प्रयागराज क्षेत्र के विभाग प्रमुख राधेश्याम पांडे जी, जिला मंत्री रविकान्त जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री एवं उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के प्रभारी श्री राधावल्लभ त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष



आईपीएस चौहान जी आदि उच्च पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन कुंदन कुमार सिंह द्वारा किया गया। बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार विस्तार पूर्वक चर्चा हुई सभी कार्य समिति सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किया जिसमें प्रमुख निर्णय निलंबित महामंत्री श्री रूपम पांडे जी द्वारा की जा रही संगठन विरोधी गतिविधियों को लेकर

विस्तार पूर्वक बैठक में चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री श्री अनिल उपाध्याय जी ने सभी सदस्यों को बताया कि दिनांक 17 अगस्त 2026 को महामंत्री श्री रूपम पांडे को 15 दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया था। उसके उपरांत 31 अगस्त 2026 को पुनः अनुस्मारक नोटिस 7 दिन में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु प्रस्तुत किया

गया था परंतु उन्होंने अपना कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जिस कारण से यह सिद्ध हुआ है कि उनके द्वारा संगठन विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। 16 अगस्त 2026 को गठित अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी महामंत्री श्री रूपम पांडे जी द्वारा संगठन विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं ऐसा सत्य

सिद्ध हुआ है। सभी से चर्चा उपरांत बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महामंत्री श्री रूपम पांडे को महामंत्री पद से दायित्व मुक्त करते हुए 5 वर्ष के लिए संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। उनके स्थान पर संयुक्त मंत्री श्री कुंदन कुमार सिंह को महामंत्री के रिक्त पद पर कार्यसमिति द्वारा नियुक्त किया गया है और संयुक्त मंत्री पद के रूप में कार्यसमिति सदस्य श्रीमती बीना सिंह को नामित किया गया है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष निर्भय सिंह, उपाध्यक्ष रूकमानंद पांडेय, उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा, संयुक्त मंत्री बंशी बदन झा, कोषाध्यक्ष अजय सिंह कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा।

मेहंदीपुर बालाजी धाम तीर्थ यात्रा बस रवाना



समय जगत, झांसी। मां कामाख्या श्री बालाजी मंडल सेवा संस्थान झांसी रजिस्टर के तत्वाधान में श्री मां कैला देवी श्री खाटू श्याम जी श्री जीण माता धाम श्री सालासर बालाजी धाम एवं घाट मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए आठ तीर्थ यात्रा बस को मंडल प्रबंधक बी0एल0भ्यामकर ने पूजन कर रवाना किया मंडल के महंत श्री संतोष महाराज के नेतृत्व एवं अन्य पदाधिकारी अध्यक्ष मन्नालाल सेठ संगठन मंत्री किशोर वर्मा आदि के साथ तीर्थ यात्रा बस को पूजन कर रवाना किया।

तीर्थ यात्रा बस 6 दिन बाद झांसी वापस आएगी। मां कामाख्या श्री बालाजी मंडल के प्रबंधन बीव एलवभास्कर एडवोकेट ने बताया की तीर्थ यात्रा सबसे पहले श्री मां क ला देवी धाम करौली से दर्शन करने के बाद श्री खाटू श्याम जी पहुंचेंगी, संगठन की विचारधारा एवं प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण में कैडेट्स ने झोन की बारीकियों को समझा

समय जगत, झांसी। 56 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी झांसी द्वारा चलाए जा रहे एनसीसी के वार्षिक शिविर 196 के तीसरे दिन कैडेट्स को झोन तकनीक की बारीकियों से रूबरू कराते हुए झोन इंस्ट्रक्टर श्री राकेश राजपूत ने बताया कि आने वाला समय झोन तकनीक का होगा। उनके साथ जयपुरिया स्कूल के कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों ने एनसीसी कैडेट्स के समझ झोन की असेंबलिंग की और झोन को उड़ा कर दिखाया जिससे कैडेट्स झोन तकनीक को सीखने हेतु प्रेरित हुये। इस अवसर पर डिप्टी कैप्ट कमांडेंट कर्नल अंशुमन सक्सेना ने कैडेट्स से झोन तकनीक को सीखने पर जोर दिया।

यात्रा जीण माता धाम पहुंचेगी वहां से श्री सालासर बालाजी धाम चुर राजस्थान जाएगी वहां विश्राम, दर्शन उपरांत सभी तीर्थयात्री मेहंदी पुर बालाजी धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और तीन दिन तक मेहंदीपुर बालाजी घाटे में रख कर श्री बालाजी महाराज के चरणों में देश की सुख शांति एवं परिवार की सुख शांति के लिए अर्जी लगाएंगे हवन पूजन भंडारा करेंगे इसके बाद झांसी के लिए प्रस्थान करेंगे मंत्री किशोर वर्मा आदि के साथ तीर्थ यात्रा बस को पूजन कर रवाना किया। तीर्थ यात्रा बस 6 दिन बाद झांसी वापस आएगी। मां कामाख्या श्री बालाजी मंडल के प्रबंधन बीव एलवभास्कर एडवोकेट ने बताया की तीर्थ यात्रा सबसे पहले श्री मां क ला देवी धाम करौली से दर्शन करने के बाद श्री खाटू श्याम जी पहुंचेंगी, संगठन की विचारधारा एवं प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में 'सेवा ही संकल्प, राष्ट्र ही सर्वोपरि' की भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने का संकल्प लिया।कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

मेला जलविहार समिति की हुई बैठक



समय जगत, झांसी। मेला जलविहार समिति झांसी की बैठक सिद्धेश्वर मंदिर में हुई। इसमें गणेश उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की समितियों से अपील की गई कि वह प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की प्रतिमा को स्थानीय बार-बार आग्रह करने के बाद भी रैम्प का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। यह स्थिति तब है, जब पीछे की बाउंड्री पूरी टूटी है और शेष में बारिश का पानी समाया हुआ है।

इस दौरान अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री पिपूष रावत, संरक्षक महंत विष्णु दत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक, आचार्य वसंत विष्णु गोलवर्कर, आचार्य लल्लु महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, आचार्य मनोज चतुर्वेदी, महेश श्राफ मटका, जगदीश गुप्ता वरिष्ठ, आचार्य विनोद अवस्थी, गोकुल दुबे, अतुल किलपन, रवीश त्रिपाठी, राजीव तिवारी, पवन गुप्ता, राजीव तिवारी, प्रभात शर्मा, पुरेकेश अमर्या, अभिषेक साहू, अतुल मिश्रा, आदि मौजूद रहे। पीपूष रावत और राजीव पाठक ने संयुक्त रूप से आभार व्यक्त किया।

तारीख पेशी- 21/09/2026

अदालत श्रीमान सिविल जज जू.डि. गरौठा झांसी

वाद सं.- 26 सन- 2026 अशोक कुमार आदि बनाम सर्वसाधारण, मुकाम गरौठा जिला झांसी दरखास्त मुसक्का अशोक कुमार आदि वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट बसूल जर कर्जा व किफालत हाय यापतानी मुसम्मा सर्वसाधारण मुतबक्फा अशोक कुमार आदि अपने बसूलिब एक्ट 7 सन 1889 ई. वकैद हरगाह मुसम्मा अशोक कुमार ने दरखास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और 21 तारीख माह 09 सन 2026 ई. के वास्ते समआत दरखास्त के मुकुरर हुई ई. लिहाजा यह इश्तहार जारी किया जाता है कि जिस किसी को नस्वत दरखास्त के उज हो या असालतन या बकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज जू.डि. मुकाम गरौठा व तारीख मुकरंह हाजिर होकर उज अपना पेश करे। दरसरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर जज किसी का सुना न जाएगा और हुकम मुनासिफ निश्चत दरखास्त मजकूर के सादिर होगा अलमरकूम 21/08/ 2026 ई. मुंसरिम सिविल जज जू.डि. गरौठा, जिला- झांसी

मुख्यमंत्री ने लाडवा के शिवाला रामकुंडी में आयोजित श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी महोत्सव में की शिरकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए शिखरों की ओर बढ़ रहा है भारत

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पर चलते हुए युवा आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ें। दुनिया में हर क्षेत्र में हरियाणा और भारत का नाम रोशन करें। साथ ही अपने संस्कारों, संस्कृति और अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। युवाओं के जीवन में आधुनिकता, मर्यादा, प्रतिभा, विनम्रता, सफलता और सेवा का भाव भी हो। यही हमारी संस्कृति की ताकत है और यही विकसित भारत-विकसित हरियाणा की मजबूत नींव बनेगी। मुख्यमंत्री लाडवा, कुरुक्षेत्र के शिवाला रामकुंडी में आयोजित श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी महोत्सव में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी की

देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने वामन द्वादश मेला समिति को 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जन्म अष्टमी हमारे लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य, साहस, प्रेम और लोक-कल्याण के उस महान संदेश का उत्सव है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण जी ने अपने जीवन के माध्यम से मानव मात्र को दिया। काह्ना का जन्म हमें यह विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, अन्याय कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग है तो आखिर में सफल उसी की होती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ। परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। चारों ओर अन्याय का वातावरण था, लेकिन उसी अंधकार के बीच आशा की एक किरण ने जन्म लिया

और वह किरण आगे चलकर अधर्म के अंत का कारण बनी। यही जन्म अष्टमी का सबसे बड़ा संदेश है कि अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, प्रकाश को जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण जी ने कभी जीवन से पलायन का संदेश नहीं दिया। उन्होंने चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। अन्याय के सामने मौन रहना धर्म नहीं है। जो सही है, उसके पक्ष में खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण जी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि महानता पद में नहीं, व्यवहार में होती है। भगवान होकर भी उन्होंने सुदामा की मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने गोवर्धन उखार समाज की रक्षा की। उन्होंने द्रोपदी की पुकार सुनी। उन्होंने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। उनका पूरा



जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख-दुख में सहभागी बनता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम उस कुरुक्षेत्र की पवित्र धरा का हिस्सा हैं, जहां भगवान श्रीकृष्ण जी ने

पूरी मानवता को श्रीमद्भगवद् गीता के माध्यम से कर्म योग का अमर संदेश दिया। यह वही भूमि है, जहां मोह में पड़े अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण जी ने कर्म का मार्ग दिखाया। इस भूमि पर रहना हमारे लिए गर्व की बात है। जीवन में कठिनाई देखकर कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करते जाना है। भरे लिए भी सार्वजनिक जीवन में गीता का यही संदेश प्रेरणा का स्रोत रहा है। जनसेवा मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही मेरा धर्म है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण जी का जीवन आपके लिए भी विशेष प्रेरणा है। युवा अवस्था केवल आयु का नाम नहीं, ऊर्जा, संकल्प और साहस का नाम है। श्रीकृष्ण जी ने युवा अवस्था में ही अत्याचार का सामना किया। समाज को संगठित किया और धर्म की स्थापना के लिए कठिन से कठिन निर्णय

लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हमारे युवाओं के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। प्रतिस्पर्धा है, भटकाव है, नशे और नकारात्मकता का खतरा है। ऐसे समय में गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। युवा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। मेहनत कीजिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखिए। नशे से दूर रहिए और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाइए। जिस दिन युवा अपने भीतर की शक्ति पहचान लेंगे, उस दिन आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए विकास के नए शिखरों की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि आधुनिक विकास और प्राचीन संस्कृति एक-दूसरे के पूरक हैं। एक ओर

देश डिजिटल तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष और आधुनिक बुनियादी ढांचे में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारी आस्था, परंपराएं तथा सांस्कृतिक विरासत नए आत्म-विश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रतिष्ठित हो रही हैं। यही नया भारत है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और भविष्य की ओर आत्म-विश्वास से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता किसी जन-प्रतिनिधि पर विश्वास करती है तो वह विश्वास उसे दिन-रात जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलते हुए कहा कि लाडवा के विकास, सुविधाओं के विस्तार और यहां के प्रत्येक परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है और आगे भी ऐसी ही चलता रहेगा। इस अवसर पर विभिन्न स्कूली छात्रों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया।

सार-समाचार

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर सरकार का विशेष जोर : मुख्यमंत्री



चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर, आधुनिक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को भी लगातार मजबूत कर रही है, ताकि आमजन को गंभीर बीमारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सचिवालय में स्टेट फाइनंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फेज-2 विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थीं। फेज-डब्लू के तहत अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं और क्षमता में बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इससे करनाल सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हर वर्ष 120 एमबीबीएस विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है तथा 64 पीजी सीटें हैं। अस्पताल में करीब 600 बेड की क्षमता है। फेज-2 के तहत अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए 404.95 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत ट्रॉमा सेंटर, बर्न सुनिट एवं बर्न वार्ड, आईसीयू, आईसीसीयू, जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और मनोरोग विभाग से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा हेलिपैड तथा अन्य जरूरी सहयोगी एवं सहायक सुविधाओं का भी प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित विस्तार के तहत अस्पताल में करीब 505 नए बेड जोड़े जाएंगे। इससे अस्पताल की कुल बेड क्षमता लगभग 600 से बढ़कर 1100 बेड हो जाएगी। इससे गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं और अन्य जटिल मामलों के मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी और क्षेत्र में विशेषज्ञ एवं सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिला क्षमता को 120 सीटों से बढ़ाकर 250 सीट करने का प्रस्ताव है। इससे मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए संस्थान की क्षमता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। फेज-डब्लू के तहत कुछ निर्माण कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 169.58 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त हॉस्टल और आवासीय सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, अस्पताल परिसर के फेज-डब्लू विस्तार का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। फेज-2 विस्तार के माध्यम से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य में शैक्षणिक, वलीनिकल और सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार के लिए भी आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार होगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राठौर कुमार गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री सीजी रजनी कौशन, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक श्री धीरेन्द्र खरगटा सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ने शुरु किया रिहसल

गुरुग्राम। जैकबपुरा स्थित श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ने वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए इस वर्ष भी रामलीला के मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमेटी के प्रधान कपिल सलूजा का कहना है कि आगामी 24 सितंबर को भूमि पूजन किया जाएगा और 9 अक्टूबर से जैकबपुरा स्थित रामलीला मैदान परिसर में रामलीलाओं का मंचन शुरू होगा। रामलीला में विभिन्न पात्रों का किरदार निभाने के लिए कलाकार रिहसल में गुट गए हैं। पात्रों द्वारा संवाद, संगीत और अभिनय का गहन अभ्यास आधी रात तक पूरी लगन से किया जा रहा है ताकि दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया जा सके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दर्शकों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए कई नए और आकर्षक बदलाव किए गए हैं। मनमोहक झाड़ियां भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। गत वर्ष की तुलना में इस बार रामलीला भव्य और आकर्षक होगी। कमेटी अनुभवी कलाकारों के साथ-साथ नए और उभरते कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रही है, ताकि यह सांस्कृतिक विरासत भविष्य में भी फलती-फूलती रहे।

प्रदेश में बनेंगे 582 ‘विलेज नॉलेज सेंटर, ग्रामीणों को मिलेगी एक ही स्थान पर सुविधा

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का मकसद ग्रामीणों को भी शहरों जैसी बेहतर और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सरकार गांवों के विकास पर लगातार काम कर रही है, सरकार के प्रयास हैं कि हर तरह की सुविधा ग्रामीण इलाके में भी मिले। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सचिवालय में स्टेट फाइनंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों द्वारा नाबाई के सहयोग से प्रदेश में 582 विलेज नॉलेज सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस परियोजना पर कुल 514.53 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक विलेज नॉलेज सेंटर पर लगभग 88.33 लाख रुपये खर्च होंगे। इस दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि इस परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय प्रदान की जाए, ताकि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित हो सके। विलेज नॉलेज सेंटर को गांव में एक ‘ऑल-इन-वन’ सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विकास एवं

पंचायत विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी उपलब्ध रहे। इससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से संबंधित आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाएं सुगमता से मिल सकेंगी। इनमें बैठक कक्ष, सरपंच कार्यालय, सीएससी रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, केयर टेकर कक्ष जैसी सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ‘विलेज नॉलेज सेंटर’ परिसर में चबूतरे के साथ एक छायादार पेड़ भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में चबूतरा और पेड़ हमेशा से ही आपसी मेल-जोल, बातचीत और सामुदायिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। इसी पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते हुए विलेज नॉलेज सेंटर परिसर में ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि यह केंद्र केवल सरकारी सेवाओं का स्थान न रहकर ग्रामीणों के लिए बैठने, संवाद करने और आपसी मेल-जोल का सुविधाजनक सामुदायिक स्थल भी बन सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांवों के विकास में बुनियादी सुविधाओं का बेहतर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों की रिपेयरिंग का उचित प्रावधान किया जाए।

खेल प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाएंगे दो हजार रुपये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दी गई मंजूरी

दिल्ली, समय जगत। दिव्हे के सरकारी स्टेडियमों व स्पोर्ट्स सेंटers में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों को अब हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रासरूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंस शुरू करने को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण ग्रासरूट स्तर पर खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से यह सहायता दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल खिलाड़ी अपनी खुराक, स्थानीय परिवहन, छोटे खेल उपकरण और चिकित्सा जैसी जरूरतों के लिए कर सकेंगे। योजना के दायरे में अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 के साथ-साथ अंडर-21 आयु वर्ग के खिलाड़ी भी आएंगे।



योजना के तहत किसी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नामांकित प्रशिक्षुओं में से अधिकतम 25 प्रतिशत को सहायता मिलेगी। सामान्यतः एक सेंटर से अधिकतम 100 खिलाड़ी इसके दायरे में होंगे। बड़े स्टेडियमों में बजट उपलब्ध होने पर संख्या 150 तक बढ़ाई जा सकेगी। खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन, अनुशासन व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर होगा। प्रशिक्षुओं की 80व उपस्थिति अनिवार्य होगी।

गुरुग्राम-1 के एफएसओ नियुक्त हुए मनोज कुमार

गुरुग्राम। जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अब दो नए फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) मिल गए हैं। मनोज कुमार को गुरुग्राम-1 और डॉ. दीपक को गुरुग्राम-2 का एफएसओ नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी वेटरनरी सर्जन हैं। गुरुग्राम के फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ डॉ. रमेश कुमार के तबादले के बाद जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त प्रभार के सहारे चल रही थी। रेवाड़ी के एफएसओ संदीप कुमार को गुरुग्राम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

गौ अभ्यारण्यों में फेंसिंग व चारदीवारी के साथ हरे चारे की व्यवस्था के निर्देश

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर बेसहारा पशुओं को पकड़ा जाए तथा प्रत्येक पशु की टैगिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं की पहचान सुनिश्चित होने से यदि किसी घर या गौशाला से पशु बाहर आता है तो संबंधित पशुपालक की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सचिवालय में गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की समस्या, गौशालाओं की व्यवस्थाओं, गौ अभ्यारण्यों, नस्ल सुधार

तथा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों और हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री रामचंद्र कंबोज ने बेसहारा पशुओं और गौशाला में मौजूद गौवंश पर अपनी बात रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में अभियान चलाकर प्रत्येक गौवंश की टैगिंग की जाए। नगर निकायों द्वारा पकड़े जाने वाले पशुओं को गौशालाओं में छोड़े सभ्य भी उनकी टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि प्रत्येक पशु की पहचान सुनिश्चित हो सके। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कई बार कुछ पशुपालक सुबह और शाम पशुओं का दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पशु सड़कों



पर बेसहारा अवस्था में नजर आते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पशुपालक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने पर चर्चा हुई। इस दौरान पहली बार पशु पकड़े जाने पर 11 हजार रुपये, दूसरी

बार 21 हजार रुपये का जुर्माना तथा तीसरी बार पशु पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किए जाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ऐसे पशुपालकों को सरकार की ओर से पशुओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं, जैसे वैकसीनेशन, इश्योरेस प्रीमियम आदि से वंचित करने तथा उनका नाम नेगेटिव लिस्ट में डालने की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पकड़े गए पशुओं को निर्धारित कार्रवाई किए बिना वापस नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जिला वार टेंडर करने के निर्देश दिए, ताकि विशेष अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। मुख्यमंत्री ने गौ

अभ्यारण्यों की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में उचित फेंसिंग करवाई जाए। जिस क्षेत्र में पशुओं को रखना है, वहां चारदीवारी की व्यवस्था की जाए तथा शेष क्षेत्र में हरे चारे की बुआई करवाई जाए। गौ अभ्यारण्यों में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने, गौवंश के बेहतर रखरखाव, नस्ल सुधार तथा गौशालाओं में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एवं सचिव श्री अंशोक मीणा, पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉ प्रेम सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

गौशालाओं के साथ सामाज्य बनाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 707 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 4 लाख गौवंश हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आबारा कुत्तों की समस्या पर भी संज्ञान लेते हुए इसके प्रभावी समाधान के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर निकाय विभाग और पशुपालन विभाग संबंधित गाइडलाइन के अनुसार समन्वय के साथ कार्य करें। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अंशोक मीणा, पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉ प्रेम सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा

हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की समर्पित जनसेवा और परिवर्तनकारी सुशासन मुहैया करवाने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ मनाया जाएगा। एक माह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देना, पात्र नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना तथा सरकारी सेवाओं को जल्दी स्तर तक पहुंचाना है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को समन्वित, समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान का प्रमुख घटक ‘सेवा सेतु’द्वारा आपके द्वार’ होगा।

इसके तहत ब्लॉक एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक

ब्लॉक एवं विधानसभा क्षेत्र में ‘सेवा सेतु केंद्र’ स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया में सहायता तथा लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्य सचिव ने विभागों को खंडवार कार्यक्रम तैयार करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच के लिए लाभार्थी डेटाबेस तैयार रखने के निर्देश दिए। युवाओं एवं बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राष्ट्रध्वजा चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थी देश के विकास की उपलब्धियों तथा बेहतर भविष्य की आकांक्षाओं से जुड़े

विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री के.एम. पांडुरंग ने बताया कि ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत नागरिकों को अपने घर, पड़ोस, गांव, स्कूल, कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थानों पर सेवा गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों का दौरा, वंचित बच्चों को शैक्षणिक सहयोग, महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण एवं एनोमिया जागरूकता, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, कचरे को अलग करना, साइबर सुरक्षा, खेल गतिविधियों तथा दिव्यांगजनों की सहायता सहित 25 सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

संपादकीय

पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है आतंकवाद पर लगाम

देश के लिये आतंकवाद लंबे समय से बड़ा मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के लिए अनुकूल माहौल जरूरी है। जिसके लिये पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। सीमा पार से आतंकियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें भारत में हिंसा फैलाने के लिए भेजना और आतंकी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना उसकी नीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर कार्रवाई की एक कीमत होती है और अब पाकिस्तान को अपने इसी रवैये की कीमत पानी के मोचें पर चुकानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो कठोर निर्णय लिया, उसके प्रभाव अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। लद्दाख में सिंधु नदी पर चेक डैम का निर्माण इसी बदलती तस्वीर का संकेत है। लद्दाख के उपशी में सिंधु नदी पर तैयार किया गया पहला रॉक चेक डैम केवल पानी रोकने वाली एक छोटी परियोजना नहीं है। यह बदलते भारत की सोच और उसकी जल नीति का प्रतीक है। जिस सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत ने दशकों तक संधि की मर्यादाओं का पालन किया, उसी नदी के पानी का अपने लोगों के हित में बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में अब कदम बढ़ रहे हैं।

उपशी में तैयार चेक डैम में पानी जमा होना और उसके माध्यम से आसपास के खेतों तक सिंचाई पहुंचने की संभावना लद्दाख जैसे दुर्गम और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुरुआत भर है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 36 और चेक डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। इनमें लेह में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल में 29 चेक डैम प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 56 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। लद्दाख की परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में पानी का संकट हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। प्राकृतिक चट्टानों से तैयार की गई ऐसी संरचनाएं पानी को रोकने, भूजल स्तर सुधारने और खेतों तक पानी पहुंचाने में उपयोगी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जा रहे इन ढांचों से जल संरक्षण और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश भी दिखाई देती है। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए तो उससे जुड़े शेष मुद्दों का समाधान भी हो सकता है।

विश्व को भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन से दिया शांति का संदेश

सौरभ वाष्णीय

पूरा विश्व इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें भारत के नई दिखी में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों की एक कुटनीतिक बैठक भर नहीं है। यह सम्मेलन बदलती हुई विश्व व्यवस्था, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता, युद्धों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और विकासशील देशों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच भारत की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडल में होने वाले 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बार उसका केंद्रीय विषय है (ब्रिडजिंग फॉर रिसिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) अर्थात लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण 7 भारत ने अपनी अध्यक्षता को ह्यूमैनिटी फर्स्ट की सोच से जोड़ते हुए ब्रिक्स को अधिक व्यावहारिक और विकासोन्मुख मंच बनाने पर जोर दिया है। यही इस सम्मेलन से भारत का पहला और सबसे बड़ा संदेश है- विश्व राजनीति को टकराव से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक हिस्से संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं। यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ब्रिक्स का मंच भारत को यह संदेश देने का अवसर देता है कि अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय हितों वाले देश भी संवाद और सहयोग के माध्यम से सझा समस्याओं पर काम कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति का मूल स्वर न तो किसी एक शक्ति-गुट के साथ खड़ा होना है और न किसी दूसरे गुट के विरोध में खड़ा होना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। यही रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की सबसे बड़ी कुटनीतिक ताकत बनती दिखाई दे रही है। ब्रिक्स अब केवल पांच देशों का आर्थिक समूह नहीं रह गया है। इसके विस्तार ने इसे विकासशील और उपरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है। भारत इस मंच के माध्यम से ग्लोबल साउथ की उस आवाज को मजबूती देना चाहता है, जो लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की नियंत्रण प्रक्रिया में विकासशील देशों की वास्तविक आर्थिक और जनसंख्या-आधारित ताकत के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल लगातार उठता रहा है। भारत का संदेश स्पष्ट है— 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था 20वीं सदी की शक्ति-संरचना के आधार पर नहीं चल सकती । विश्व अर्थव्यवस्था में उपरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक संस्थाओं में भी उनकी आवाज और भागीदारी बढ़नी चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सहयोग भी होगा। भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। भारत की अध्यक्षता में व्यापार मंत्रियों की बैठकों में भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विविध बनाने तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। भारत का अनुभव बताता है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना, विशेषकर डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और तकनीक आधारित सेवाएं विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए ब्रिक्स के मंच से भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि तकनीक केवल विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। भारत आज दुनिया के सामने अपनी डिजिटल क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल भुगतान को आम नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि ब्रिक्स देश डिजिटल भुगतान, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। यह भारत की उस सोच से मेल खाता है जिसमें तकनीक का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि आम आदमी का सशक्तीकरण भी है। नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भारत-चीन संबंध भी है। चीन की भागीदारी इस सम्मेलन को रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद हाल के वर्षों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह चीन के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं से समझौता न करे। यही भारतीय कुटनीति की परीक्षा है— प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग और मतभेदों के बीच संवाद भारत यह संदेश देना चाहता है कि किसी देश के साथ आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। ब्रिक्स में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

{ विचार पीठ }

दुबई में बजा मोहन का डंका, एमपी में संभावनाएं हैं अपार

नजरिया

प्रदेश में 18 नई उद्योग अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को बेहतर वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाया है। एक दौर था जब एमपी की गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी, अब उद्योगों के अनुकूल नीति और निवेश

हर्षवर्धन पांडे
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में एक नए युग का आगाज किया है। वार्षिक निवेश बैठक एआईएम कॉग्रेस 2026 में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को वैश्विक मंच पर एक सशक्त, भरोसेमंद और संभावनाओं से भरे औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दुबई दौरा राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र दुबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश क्षमताओं को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करते हुए निवेशकों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया। यह दौरा न केवल एमपी की छवि को नया रूप देने वाला रहा, बल्कि भविष्य में निवेश के लिहाज से और युवाओं को रोजगार के लिहाज से मध्यप्रदेश के लिए कई संभावनाओं के नए द्वार भी खोलेंगे। मध्यप्रदेश अपनी कई विशिष्ट पहचानों के कारण पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में 18 नई उद्योग अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को बेहतर वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाया है। एक दौर था जब एमपी की गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी, अब उद्योगों के अनुकूल नीति और निवेश की भरपूर क्षमताओं से एमपी देश के साथ ही दुनिया के निवेशकों के दिल जीत रहा है। औद्योगिक इकाईं स्थापित करने के लिए राज्य में अब केवल 29 दिन में जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। मोहन सरकार में लगभग 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। प्रदेश में ऑन द स्पॉट लैंड अलॉटमेंट हो रहा है। मध्यप्रदेश में 1 लाख से अधिक इंस्ट्रियल लैंड बैंक और 5 लाख किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क है। राज्य सरकार की निवेशकों के अनुकूल नीतियां और अनेक प्रोत्साहन राज्य में व्यापार और उद्योग की नई



संभावनाएं के द्वार खोल रही हैं जिससे निवेशक मध्यप्रदेश की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में कई प्रमुख कंपनियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। दुबई के व्यापारिक समुदाय के साथ हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जहां टैक्स ह्यूट, तेज़ मंजूरी प्रक्रिया और कुशल कार्यबल उपलब्ध है।

दुबई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों और प्रमुख उद्योग समूहों के साथ वन टू वन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 53,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। शराफ ग्रुप द्वारा रेल-साइडिंग लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 450 करोड़ रूऔर रिन्यूएबल एनर्जी व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। वैश्विक लॉजिस्टिक्स दिग्गज डीपी वर्ड नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय चर्चा में पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कंपोजिट हब को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग सुविधाओं के साथ एक प्रमुख इनलैंड

खेतों में फसल, आसमान में उतरेगी ऊर्जा

विनोद सिंह

भारत के खेत अब केवल अब पैदा करने तक सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले समय में यही खेत देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेत की मिट्टी में फसल लहलहाए और उसी खेत के ऊपर लगे सौर पैनल स्वच्छ बिजली पैदा करें कृषि और ऊर्जा के इस नए संगम को एग्रीवोल्टिक्स कहा जा रहा है। यह अंधाधुंगा भारत जैसे देश के लिए विशेष महत्व रखती है, जहाँ एक ओर बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में 7वें एग्रीवोल्टिक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के कर्टेन रेजक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दिशा में भारत की भावी नीति का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जिस किसान ने हल्सा देश का पेट भर है, वहीं अब देश को रोशन भी कर रहा है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन रहा है। यह कथन केवल एक भावनात्मक संदेश नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर किसानों की आय में स्थिरता लाने की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम- कुसुम के अगले चरण में एग्रीवोल्टिक्स के लिए एक समर्पित घटक लाया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खेती जारी रखते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन से आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करना है। इसमें विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सरकारी समितियों और पंचायतों को केंद्र में रखा जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का स्वािमित्व किसान के पास ही बना रहे। भारत की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। ऐसे किसान सीमित भूमि पर खेती करते हैं और उनकी आय काफी हद तक मानसून बाजार भाव तथा कृषि लागत पर निर्भर रहती है। ऐसे में यदि उसी भूमि से निर्भर सौर ऊर्जा आय का एक नया स्रोत जुड़ जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। एग्रीवोल्टिक्स का मूल विचार भी यही है कि किसान को फसल और सौर ऊर्जा में से किसी एक का चुनाव न करना पड़े। सौर पैनलों को इस तरह स्थापित किया जाए कि उनके नीचे या आसपास खेती जारी रह सके। यानी जमीन पर फसल और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी से बिजली एक ही स्रोत से दोहरा ली जाए। यही मॉडल सीमित कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। डॉ. जोशी ने एक एकड़ जमीन से



किसान की संभावित तीन आय धाराओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। पहली आय खेत में पैदा होने वाली फसल से होगी। दूसरी आय सौर ऊर्जा को डिस्कॉम को बेचने से प्राप्त हो सकती है। तीसरा लाभ डीजल आधारित सिंचाई की जगह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाली बचत के रूप में सामने आएगा। इस प्रकार सौर ऊर्जा किसान के लिए केवल अतिरिक्त कमाई नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का साधन बन सकती है। भारत की जनसंख्या और भूमि का अनुपात भी एग्रीवोल्टिक्स की उपयोगिता को स्पष्ट करता है। भारत में विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि विश्व की कुल भूमि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.4 प्रतिशत है। देश के 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं और दो हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषि भूमि का ऐसा उपयोग, जिसमें खाद्य उत्पादन प्रभावित किए बिना ऊर्जा उत्पादन भी किया जा सके, आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी ओर भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। देश ने पिछले वर्ष 55.29 गीगा वाटौर गीगावश्र ऊर्जा क्षमता जोड़ी। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सौर ऊर्जा इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है। कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा को लाभार्थि बना दे रहा है। पीएम- कुसुम के तहत लगभग 29 लाख कृषि पंपों का सोलरीकरण किया जा चुका है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। पिछले वर्ष विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा ने कुल 16.3 गीगावाट का योगदान दिया, जिसमें पीएम- कुसुम से 7.6 गीगावाट और रूफटॉप सोलर से 8.7 गीगावाट शामिल हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को संख्या भी करीब 56 लाख तक पहुंच रही है। हालाँकि एग्रीवोल्टिक्स को केवल सौर पैनल लगाने

की सामान्य तकनीक मानना उचित नहीं होगा। कृषि और सौर ऊर्जा दोनों की जरूरतों को साथ लेकर चलने के लिए क्षेत्रवार और फसलवार वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होंगे। हर फसल को समान मात्रा में धूप की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह देश के अलग- अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान की परिस्थितियाँ भी अलग हैं। इसलिए पैनल की ऊँचाई, उनके बीच की दूरी, दिशा, ट्रैकिंग सिस्टम और संरचना का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप करना होगा। इस दिशा में पुणे स्थित बाएफ के रूरल इनेवेशन सेंटर में 30 फसलों के साथ 17 अलग-अलग सौर बिन्यासों का परीक्षण किया जा रहा है। यह प्रयोग इस बात का उदाहरण है कि एग्रीवोल्टिक्स की सफलता के लिए अनुसंधान और प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य में यह तय करना होगा कि किस क्षेत्र में किस फसल के साथ किस प्रकार की सौर संरचना सबसे प्रभावी होगी। कृषि मशीनरी की आवाजाही भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।यदि खेत में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या अन्य कृषि उपकरण आसानी से नहीं चल पाएंगे तो किसानों के लिए एग्रीवोल्टिक्स आकर्षक मॉडल नहीं बन सकेगा। इसलिए ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता होगी जिनके नीचे कृषि कार्य सामान्य रूप से किया जा सके और जो स्थानीय मौसम की परिस्थितियों का भी सामना कर सके। इसके साथ लागत कम करना भी जरूरी होगा। सौर संरचनाओं, मॉडर्टाई सिस्टम और अन्य उपकरणों की लागत यदि अधिक रही तो छोटे किसान के लिए इस मॉडल को अपनाना कठिन हो सकता है। इसलिए उद्योग, स्टार्टअप और शोध संस्थानों को कम लागत वाली, मजबूत और किसान केंद्रित तकनीक विकसित करनी होगी। एग्रीवोल्टिक्स की सफलता के लिए कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऊर्जा क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा फसलवार तथा क्षेत्रवार आंकड़े तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इससे किसानों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनके क्षेत्र में कौन-सी फसल और कौन-सा सौर बिन्यास सबसे उपयुक्त रहेगा। इस नई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी है। भारत में लगभग 70 हजार सूर्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये प्रशिक्षित युवा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, रखरखाव और तकनीकी सहायता में भूमिका निभा सकते हैं। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। एग्रीवोल्टिक्स की संभावनाएँ केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। डॉ. जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का अनुभव ग्लोबल साउथ के उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जहाँ छोटे कृषि जोत, पर्याप्त

38 साल बाद श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे भारतीय रक्षा मंत्री

नীরज कुमार दुबे

श्रीलंका हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। कोलंबो, हंबनटोटा और अन्य बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए असाधारण महत्व देती है। पिछले वर्षों में चीन की आर्थिक और बंदरगाह परियोजनाओं ने श्रीलंका को बीजिंग के रणनीतिक प्रभाव के केंद्र में ला दिया था। करीब 38 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का श्रीलंका पहुंचना हिंद महासागर की बदलती भू-राजनीति में भारत की उस रणनीतिक वापसी का संकेत है, जिसमें सुरक्षा, समुद्री शक्ति, आर्थिक साझेदारी और जनविश्वास, चारों मोर्चों को एक साथ साधा जा रहा है। इससे पहले 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री के.सी पंत श्रीलंका गए थे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलंबो की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने कोलंबो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, उसका रणनीतिक संदेश बेहद स्पष्ट था, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका को अपना बेहद करीबी मित्र मानता है और संकट की किसी भी घड़ी में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह केवल भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि 2022 के आर्थिक संकट और 2025 में चक्रवात दिवाह के बाद भारत की त्वरित सहायता से जुड़ी उस विश्वसनीयता का राजनीतिक विस्तार है, जिसे श्रीलंका में चीन के मुकाबले भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जा सकता है।

श्रीलंका हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। कोलंबो, हंबनटोटा और अन्य बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए असाधारण महत्व देती है। पिछले वर्षों में चीन की आर्थिक और बंदरगाह परियोजनाओं ने श्रीलंका को बीजिंग के रणनीतिक प्रभाव के केंद्र में ला दिया था। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम संकेत देता है कि कोलंबो अब एकतरफा चीनी निर्भरता की बजाय विविध साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। खुद श्रीलंका के संडे टाइम्स ने राजनाथ सिंह के दौर से पहले लिखा कि भारत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्रा के दौरान हुए समझौतों को तेजी से लागू किया जाए। अखबार ने यह भी रेखांकित किया कि सिंह की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब श्रीलंका को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक सक्रियता से संचालित करना होगा। इसी अखबार के संपादकीय ने इससे भी बड़ा संकेत दिया। उसने हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच श्रीलंका को फिर से जिओपॉलिटिकल बोटेक्स में बताया और चीन के संदर्भ में पहले सामने आए सटिचंग शोष-पोतों के मुद्दे को याद किया। यानी श्रीलंका की अपनी मीडिया बहस भी यह स्वीकार कर रही है कि द्वीप की सुरक्षा और संप्रभुता अब सीधे हिंद महासागर की महाशक्ति प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। इस यात्रा का सबसे ठोस परिणाम तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के रूप में सामने आ रहा है। इनमें दोनों देशों के एनसीसी के बीच सहयोग, भारत और श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कालेजेज के बीच साझेदारी तथा श्रीलंकाई वायुसेना के भारतीय मूल के ४0 एंटी-एयरक्राफ्ट हथियारों के रखरखाव में भारत की सहायता शामिल है। भारत पहले ही 24 ऐसे हथियार श्रीलंका को दे चुका है और अब शेष छह की भी मुफ्त में सैटेनेस सहायता करेगा। यहां असली महत्व हथियारों से ज्यादा दीर्घकालिक मैनेज इंटरऑपरेबिलिटी और संस्थागत संबंधों का है। प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा और उपकरणों का रखरखाव किसी देश को केवल हथियार बेचने से कहीं ज्यादा गहरे सुरक्षा रिस्ते में बांधता है। इसके साथ ही कोलंबो बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के आईएनएस उदैगिरि की मौजूदगी ने यात्रा को स्पष्ट समुद्री आयाम भी दे दिया है। राजनाथ सिंह ने केवल रक्षा की भाषा नहीं बोली। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता, तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका को भी सामने रखा।

सेवानिवृत्त शिक्षक से एरियर निकालने के नाम पर मांगे पांच हजार, वरिष्ठ सहायक रंगेहाथ दबोचा

एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से बीएसए कार्यालय में मचा हड़कंप

पेंशन पटल के वरिष्ठ सहायक राजेश कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई शुरू

समय जगत, ललितपुर। मुख्यालय स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पेंशन पटल पर तैनात वरिष्ठ सहायक राजेश कुशवाहा को कथित तौर पर पांच हजार रुपये की रिश्त लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। कार्रवाई उस समय हुई, जब 82 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक अपने महंगाई भत्ते के एरियर की करीब 30 से 40 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। तालबेहट निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मदनमोहन नामदेव वर्ष 2007 में माताटीला क्षेत्र के वनगुवा कलां स्थित प्राथमिक विद्यालय से



सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी उम्र वर्तमान में 82 वर्ष है। सेवानिवृत्त शिक्षक के अनुसार उनका महंगाई भत्ते का एरियर करीब 30 से 40 हजार रुपये अगस्त माह में आया था। उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए वह करीब एक माह से विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। सेवानिवृत्त शिक्षक के मुताबिक पेंशन पटल पर तैनात वरिष्ठ सहायक राजेश कुशवाहा ने कथित तौर पर एरियर की धनराशि निकालने के

एवज में उनसे पांच हजार रुपये की मांग की। सेवानिवृत्त शिक्षक ने बताया कि आठ सितंबर को हुई बातचीत के बाद उन्होंने 10 सितंबर को कार्यालय आकर रुपये देने की बात कही। इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षक ने गुरुवार सुबह पूरे मामले की जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी। शिकायत के आधार पर टीम ने कार्रवाई की रणनीति तैयार की और कार्यालय में अपना जाल बिछाया। बताया गया कि तय योजना के

अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक रुपये लेकर बीएसए कार्यालय पहुंचे। इसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने पेंशन पटल के वरिष्ठ सहायक राजेश कुशवाहा को कथित रूप से पांच हजार रुपये की रिश्त लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम को कार्रवाई से कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन टीम ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई शुरू कर दी। टीम द्वारा कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई। बताया गया कि फुटेज उपलब्ध कराने में टीम को करीब एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई की जानकारी फैलते ही बीएसए कार्यालय में अप्पा-तफ्फी का माहौल बन गया। बताया गया कि दोपहर

करीब डेढ़ से दो बजे के बीच कार्यालय में तैनात कुछ कर्मचारी लंच ब्रेक का हवाला देते हुए टिफिन लेकर बाहर निकल गए। वहीं कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वरिष्ठ सहायक राजेश कुशवाहा से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया टीम द्वारा पूरी की जाती रही। दोपहर करीब दो बजे कार्यालय पहुंचे बीएसए रक्षेत्र कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि वह अभी-अभी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें दूरभाष के माध्यम से एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि टीम के सदस्यों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में दिनाभर मामला चर्चा का विषय बना रहा।



निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ समय से पूरा किया जाएगा। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संगंतात्विक मजबूती और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। महोत्सव को ऐतिहासिक एवं भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। इस अवसर पर समाजबंधुओं से आह्वान किया गया कि वे अपने तन, मन और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग प्रदान करते हुए

आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। बैठक में उपस्थित लोगों ने आयोजन को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक समाजबंधुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में एक संकेद रूप से अधिक समाजबंधुओं की उपस्थिति रही। इसी दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने आगामी भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव की तैयारियों, आयोजन के उद्देश्य और विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने बताया कि महोत्सव को लेकर समाज में विशेष उत्साह है और आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।

नवागत कमिश्नर दिलीप कुमार पहुंचे बीएमसी, भर्ती पीड़ितों का जाना हाल



समय जगत, सागर । बंडा में हुए अवैध जहरीली शराब ह्रादसे के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवागत संभागायुक्त श्री दिलीप कुमार ने पदभार संभालते ही

सीधे बुटेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचकर भर्ती पीड़ितों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर श्री दिलीप कुमार ने अस्पताल के वाडों में जाकर भर्ती

एक-एक मरीज की स्थिति देखी। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिजनों से सीधी बातचीत कर मिल रहे इलाज का फ़ैडबैक लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके बेहतर इलाज और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रभावित मरीजों के बेहतर और त्वरित उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, बीएमसी के प्रभारी डीन डॉ. अमर गंगवानी, अधीक्षक डॉ. राजेश जैन सहित डॉ. सौरभ जैन भी मौजूद रहे।

ग्राम तेरा में मौरंग माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा 22,500 घनमीटर अवैध मौरंग खनन की जांच में पुष्टि



-1.35 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का नोटिस जारी
-ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों को नोटिस

समय जगत, ललितपुर। जनपद के ग्राम तेरा में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध मौरंग खनन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 22,500 घनमीटर उपखनिज (लाल मौरंग) के अवैध उत्खनन एवं परिवहन का मामला पकड़ा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों को नोटिस जारी कर 1.35 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में सक्रिय अवैध खनन नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं लंबे समय से जारी खनन गतिविधियों को लेकर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली भी चर्चा के केंद्र में आ गई है।

ग्राप्त जानकारी के अनुसार आइजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर खनन विभाग ने ग्राम तेरा स्थित खनन स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर खुदाई के गड्ढे पाए गए, जिनमें पानी भरा हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने गड्ढों की पैमाइश कराई, जिसमें लगभग 90 मीटर लंबाई, 50 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर गहराई में खनन किए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र से करीब 22,500 घनमीटर लाल मौरंग का अवैध खनन एवं परिवहन किया गया।

खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया यह अवैध खनन ग्राम प्रधान बिंदे अहिरवार, बाँबी राजा खोखरा तथा मचकुन्द राजा द्वारा कराए जाने की बात सामने आई है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इन व्यक्तियों को अवैध खनन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिकायतकर्ता चंदन सिंह की उपस्थिति में किए गए निरीक्षण के

आधार पर रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी गई थी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत अवैध खनन से राजस्व को हुई क्षति की भरपाई के लिए एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) की धनराशि निर्धारित की गई है। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने तथा साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। खनन मामिलाओं के खिलाफ प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में अवैध मौरंग उत्खनन की शिकायतें की जा रही थीं। अब जांच में बड़े पैमाने पर खनन की पुष्टि होने के बाद संबंधित

आइजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर खनन विभाग ने ग्राम तेरा स्थित खनन स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर खुदाई के गड्ढे पाए गए, जिनमें पानी भरा हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने गड्ढों की पैमाइश कराई, जिसमें लगभग 90 मीटर लंबाई, 50 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर गहराई में खनन किए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र से करीब 22,500 घनमीटर लाल मौरंग का अवैध खनन एवं परिवहन किया गया।

लंबे समय से चल रहा था अवैध खनन, शिकायत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई

जनपद में लंबे समय से दबावों के संरक्षण में कथित रूप से अवैध खनन का खेल चलता रहा। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद खनन गतिविधियां नहीं रुकीं, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में दिन-रात खनन कार्य होता रहा, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अवैध खनन लंबे समय से जारी था तो खनिज विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे खनन के बावजूद विभागीय अधिकारी आखें मूंद रहे। अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों को उम्मीद है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदार अधिकारियों तथा अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई कई बड़े लोगों के नाम चर्चा में

अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की हालिया कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान बाँबी राजा और मुचकंद राजा के नाम सामने आने की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों व्यक्ति ग्राम तेरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से दबावों के बल पर अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। क्षेत्र में लगातार खनन होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और सरकारी राजस्व को भी क्षति पहुंची है। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कार्रवाई नोटिसों तक ही सीमित रही। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद भी अवैध खनन का कार्य नहीं रुका और संबंधित लोग लगातार खनन गतिविधियों में संलिप्त रहे। इसको लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो अवैध खनन इतने लंबे समय तक जारी नहीं रह पाता। जिला प्रशासन की ताजा कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवैध खनन में शामिल लोगों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद यह मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं।

लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले पर जिले भर की निगाहें टिकी हुई हैं और आगामी कार्रवाई को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है।

दुकान खुलवाने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का आरोप

समय जगत, ,ललितपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र के चौबयाना निवासी चंद्रशेखर दुबे पुत्र स्व.रामकिशन दुबे ने कटरा बाजार की जड़ौबूटी लाइन में किराने की दुकान संचालित करने वाले दीपक जैन व उसके भाई संजू जैन के खिलाफ धोखाधड़ी कर दो

लाख रुपये लेने तथा रकम वापस मांगने पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को किराने की दुकान संचालित करने जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

निवाड़ी जिला सर्वोदय मंडल के संयोजक बने कैलाश रावत



जी को बनाया गया है। अध्यक्ष सर्वोदय नेता श्री लाल सिंह गौर जी को नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियों पर जिले के कार्यकर्ता समाज से भी और सर्वोदयों ने शुभकामनाएं दीं।

बीएसए के औचक निरीक्षण में विद्यालयों की खुली पोल शिक्षामित्र व शिक्षक मिले अनुपस्थित

समय जगत, ललितपुर। बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं और विद्यालयों में शिक्षण कार्य की हकीकत जानने के लिए बीएसए रक्षेत्र कुमार ने विकास खंड तालबेहट के विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहीं पठन-पाठन एवं व्यवस्थाओं में संतोषजनक मिली तो कई विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही, अनुपस्थिति, गंदगी, खराब शौचालय, उपस्थिति पंजिकाओं में अनियमितता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में कमी जैसी गंभीर खामियां सामने आईं। बीएसए ने संबंधित विद्यालयों के जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने सुबह 8.20 बजे कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय ककडगरी का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रार्थना स्थल पर केवल एक शिक्षक की मौजूदगी में प्रार्थना कराई जा रही थी, जबकि अन्य शिक्षक कक्षा में बैठे पाए गए। शिक्षामित्र रजनी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिलीं। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी मात्र 25 रही। विद्यालय का भौतिक परिवेश असंतोषजनक पाए जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण तलब किया गया। सुबह 8.35 बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय महहौरसर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक सिता तिवारी उपस्थित मिलीं और बच्चे प्रार्थना करते पाए गए। इसके बाद सुबह 8.40 बजे पीएमश्री विद्यालय प्राथमिक स्तर महहौरसर का निरीक्षण किया गया। यहां बच्चों को योगाभ्यास कराया जा रहा था। बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक रही और विद्यार्थी गणवेश में मिले।

समय जगत, ललितपुर। गणेश महोत्सव को लेकर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। मूर्तिकार दिन-रात भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। नगर में करीब 84 स्थानों पर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित किए जाने की तैयारी है, वहीं घर-घर भी प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। इसी क्रम में शहर के कटरा बाजार में इस वर्ष भी मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की तर्ज पर गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा विराजमान होगी। कटरा बाजार में गणेश उत्सव की यह परंपरा करीब 41 वर्ष पुरानी है। वर्ष 1986 में शुरू हुई गणेश प्रतिमा स्थापना की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। गणेश महोत्सव के दौरान कटरा बाजार की झांकी जिलेभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन



करते हैं और मनोकामना पूर्ति की आस्था के साथ पूजा-अर्चना करते हैं।

मुंबई का गणेश महोत्सव देखकर आया था विचार: आयोजकों के अनुसार कटरा बाजार निवासी रामस्वरूप दाऊ मुंबई गए थे। वहां उन्होंने गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन और गणपति प्रतिमाओं की सजावट देखी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथी पुत्तन सोनी, चंद्रभान और मधुसू प्रसाद सोनी के साथ कटरा बाजार में भी गणेश प्रतिमा स्थापित करने की इच्छा जताई। उस समय ललितपुर में गणेश प्रतिमाओं

का निर्माण व्यापक रूप से नहीं होता था। ऐसे में ज्वैलर्स और पहलवान के नाम से प्रसिद्ध राम सोनी ने गणेश प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने पहली बार आकर्षक और विशाल मिट्टी की गणेश प्रतिमा तैयार की, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। इसके बाद उन्होंने चारा और घास आदि का प्रयोग कर भी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया। धीरे-धीरे कटरा बाजार का गणेश उत्सव एक प्रमुख धार्मिक आयोजन के रूप में पहचान बनाने लगा।

चार वर्षों से लालबाग के राजा की तर्ज पर स्थापना :

आयोजकों के मुताबिक पिछले चार वर्षों से कटरा बाजार में मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार की गणेश प्रतिमा मुंबई से तीन दिन पहले मंगाई गई है। प्रतिमा को आकर्षक रूप देने के लिए विशेष रूप से चांदी के आभूषण तैयार कराए गए हैं। भगवान गणेश को चांदी का मुकुट, आशीर्वाद मुद्रा वाला चांदी का हाथ का पंजा, चांदी के कड़े और चांदी के पैर पहनाए जाएंगे। इन विशेष आभूषणों से गणपति बप्पा की भव्यता और बढ़ेगी। झांकी को भी आकर्षक रूप देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

डोल ग्यारस पर विमानों की महाआरती बनेगी मुख्य आकर्षण : कटरा बाजार की गणेश झांकी में डोल ग्यारस का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। डोल ग्यारस पर नगर के विभिन्न मंदिरों से भगवान के विमान सुमेरा तालाब पहुंचते हैं। यहां विमानों में विराजमान

भगवान बांके बिहारीजी का गंगाजल से विहार कराया जाता है। इसके बाद वापस लौटते समय नगर के विमान कटरा बाजार स्थित गणेश झांकी पर पहुंचते हैं। यहां भगवान गणेश की आरती के साथ भगवान बांके बिहारीजी का भव्य पूजन और महाआरती की जाती है। इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा बाजार पहुंचते हैं। बताया जाता है कि पहले डोल ग्यारस के विमान गणेश झांकी पर नहीं आते थे। गणेश महोत्सव समिति के आग्रह के बाद यह परंपरा शुरू हुई, जो अब गणेश उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

रात्रि में भी पंडाल की रहेगी व्यवस्था : गणेश झांकी पर प्रतिदिन रात्रि में 10 से 15 लोगों का दल रुककर व्यवस्था संभालेगा। सुबह और शाम श्रीगणेश पंडाल में विधि-विधान से पूजन और भव्य महाआरती होगी। आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा

व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सराफ व्यापार संगठन अध्यक्ष मजजू सोनी ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। मुंबई की तर्ज पर गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के साथ धार्मिक परंपरा को भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है।

यह लोग संभाल रहे आयोजन की जिम्मेदारी

कटरा बाजार गणेश उत्सव की तैयारियों में मजजू सोनी, देवेन्द्र सोनी, गिरीश पाठक सोनू, राम पहलवान, लक्ष्मीनारायण सोनी, राजू सोनी, नवल किशोर सोनी, श्रीकांत करौलिया और वीरू सोनी सहित अन्य सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। समिति सदस्यों का कहना है कि चार दशक से अधिक पुरानी इस परंपरा को आगे भी पूरी श्रद्धा, भव्यता और उत्साह के साथ जारी रखा जाएगा।

समस्या बताने आए ग्रामीणों से बीच में छीना माइक,जनविश्वास शिविर से उठा जनता का विश्वास

नाराजगी के बीच एसीएस ने छोड़ा मंच

आगर मालवा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के उद्देश्य से शुक्रवार को ग्राम कराडिया में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उस समय स्थिति असहज हो गई, जब अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखने पहुंचे ग्रामीणों से बीच में ही माइक ले लिया गया। पहले ग्रामीण पीरूलाल यादव और बाद में प्रेम यादव अपनी-अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रख रहे थे। दोनों ग्रामीणों की शिकायत पूरी होने के दौरान माइक ले लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद

ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दी और इसी बीच एसीएस संजय दुबे मंच से चले गए। शिविर में एसीएस संजय दुबे के साथ कलेक्टर डॉ. शेरसिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी, विधायक मधु गहलोत, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय सहित जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव मौके पर निराकरण करना बताया गया था।

पीरूलाल यादव ने रखीं गांव की मूलभूत समस्याएं: शिविर में ग्रामीण पीरूलाल यादव ने माइक लेकर अपनी बात अधिकारियों के सामने रखनी शुरू की। उन्होंने गांव में शौचालय की समस्या के साथ सड़क, नाली सहित अन्य मूलभूत



सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। पीरूलाल अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष बता ही रहे थे कि इसी दौरान उनसे माइक ले लिया गया। इससे मौके पर

मौजूद ग्रामीणों के बीच नाराजगी का माहौल दिखाई दिया।

बिजली की शिकायत लेकर पहुंचे प्रेम यादव: इसके बाद ग्रामीण प्रेम यादव ने बिजली से संबंधित अपनी समस्या

अधिकारियों के समक्ष रखना शुरू किया। वे अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान उनका भी माइक ले लिया गया। एक के बाद एक दो ग्रामीणों से माइक लिए जाने के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों की नाराजगी और स्पष्ट

दिखाई देने लगी। शिविर में कुछ समय के लिए माहौल असहज हो गया।

ग्रामीणों की नाराजगी के बीच एसीएस ने छोड़ा मंच: ग्रामीणों की नाराजगी के बीच एसीएस संजय दुबे कार्यक्रम के दौरान ही मंच से चले गए। इसके बाद शिविर की कार्यवाही आगे जारी रही।

जनविश्वास शिविर की व्यवस्था पर उठे सवाल: जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान करना है। ऐसे में शिकायत रखने के दौरान ग्रामीणों से माइक लिए जाने की स्थिति ने शिविर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याएं सड़क, नाली, शौचालय और बिजली जैसी

बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हैं। ऐसे मामलों में ग्रामीणों की शिकायत सुनकर संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश देना शिविर की मूल भावना मानी जाती है। कराडिया के घटनाक्रम के बाद अब सवाल यह है कि जनसमस्या निवारण के लिए आयोजित शिविर में क्या शिकायतकर्ता को अपनी बात पूरी और स्पष्ट रूप से रखने का पर्याप्त अवसर मिला? साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि पीरूलाल यादव, प्रेम यादव और अन्य ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और उनका समाधान कब तक होता है। क्योंकि जनविश्वास केवल शिविर आयोजित करने से नहीं, बल्कि जनता की बात सुनने और उसकी समस्या के समाधान से कायम होता है।

मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

जुलाई से अब तक 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड

सिवनी। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। जुलाई 2026 से अब तक अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही दूध एवं विभिन्न खाद्य सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दूध विक्रेताओं, डेयरी यूनिटों एवं विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया एवं स्वच्छता की स्थिति की जांच की जा रही है। इसी क्रम में 08 सितंबर 2026 को अभिहित अधिकारी डॉ. पंकज दुबे द्वारा ईडियन कॉफी हाउस की किचिन एवं भोजन निर्माण में उपयोग की जा रही खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा की जा रही सुधारामक कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई। इसी दिन कहानी स्थित सोनू दूध डेयरी, घंसीसर से भैंस के दूध



का नमूना लिया गया। बालाजी होटल से नमकीन, सेव पोहा एवं मैदा के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

09 सितंबर 2026 को आर.वी. दूध संकलन केंद्र, अरी में रैपिड टेस्टिंग किट की सहायता से दूध के नमूनों का मौके पर ही परीक्षण किया गया। परीक्षण में दूध मानक स्तर का पाया गया। इसके अतिरिक्त अरी-बरघाट स्थित आशीष किराना से पान पराग पान मसाला, पटेल किराना स्टोर से मूंफाली एवं मिक्स नमकीन तथा नीरज किराना स्टोर से सूजी एवं तुअर दाल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को विस्तृत जांच

के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई के क्रम में जुलाई 2026 से अब तक अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इनमें साई प्रसाद टाइगर रिसोर्ट पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण किए जाने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

हीरालाल सूर्यवंशी, भटेखारी किराना स्टोर तथा पवन शिवहरे, धूमा

द्वारा बिना पंजीयन खाद्य कारोबार किए जाने पर दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। मनोहर अमृत तुल्य चाय, सिवनी पर अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय के मामले में 10 हजार रुपये तथा अभिषेक बघेल द्वारा गुटखा विक्रय किए जाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार किशोरी लाल यादव, दूध विक्रेता, पुनवारा लखनानंदैन पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिवनी ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की जा रही है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग किट से मौके पर परीक्षण के साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भी जांच कराई जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवमानक सामग्री के विक्रय, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण तथा बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

पंचायतों में गंभीर गड़बड़ी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

मुरैना। जिले में पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों की वित्तीय गुणवत्ता की कमी एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

कलेक्टर लोकेश कुमार जागड़ के निर्देश पर जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर 5 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री सहित अन्य संबंधितों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जांच एवं प्रतिवेदनों में ग्राम पंचायत इमलिया, शहदपुर, अग्रोता, रंछौरपुरा, भदावली, बरेंड, ऐसाह एवं टिकटोली दूमदार सहित अन्य पंचायतों में अनियमितताएं सामने आने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का उद्देश्य पंचायतों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत इमलिया में

मृतक के जॉब कार्ड एवं पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि किए बिना राशि का भुगतान किए जाने की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती मधु रामपुरे तथा ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी पंचायत सचिव आदिराम मावई को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। इसी प्रकरण में सरपंच श्रीमती गुड्डि पत्नी राकेश बघेल के विरुद्ध अनियमित

भुगतान एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत श्रवदपुर में मृत व्यक्ति के जॉब कार्ड पर डिमांड जलने, निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरण के आरोप में ग्राम रोजगार सहायक श्री विनोद कुमार को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। ग्राम पंचायत बरेंड एवं वर्तमान ग्राम पंचायत हुसेनपुर में बिना निर्माण कार्य कराए राशि आहरण किए जाने के मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव महेश चन्द्र जाटव को निलंबित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 2 लाख कीमत की 2 भैंसों की गई बरामद

पुलिस ने किया पशु चोरी की घटना का खुलासा

समय जगत, मुरैना। जिले में चोरी, नकबजनी और पशुधन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीना के निर्देशन में थाना सिविल लाईन पुलिस ने चोरी गए पशुधन को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 20 सितंबर 2025 को फरियादी ऋषिकेश सिंह पुत्र रमेशचन्द्र प्रजापति ने थाना सिविल लाईन में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर के पीछे बने बाड़े में बंधी भैंसों को कोई



अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्र. 413/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था। पुलिस की

सतत एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप दिनांक 11 सितंबर 2026 को थाना सिविल लाईन पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने घनेला गांव के पास जंगल से चोरी की गई 2 भैंसों (कीमती करीब दो लाख) बरामद कर लीं और उन्हें फरियादी के सुपुर्द कर दिया। इस प्रकरण में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं।

जब्त मसरूका का विवरण: प्रकरण क्रमांक 413/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत थाना सिविल लाईन क्षेत्र से कुल 02 भैंसों (कीमती लगभग 2 लाख) बरामद की गई।



मुरैना। मध्यप्रदेश शासन की मंशानुरूप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' के तहत मुरैना पुलिस ने जर्नहित में एक बेहद सराहनीय और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर के मार्गदर्शन में साइबर सेल और जिले के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने पिछले 4 महीनों में कड़े प्रयास करते हुए 401 गुप्तसूदा मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन बरामद किए गए मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 95 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिलेभर से प्राप्त गुप्त मोबाइल आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और थाना टीमों ने छद्मदृष्ट पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया। तकनीकी दक्षता और सटीक स्थानीय आसूचना के आधार पर मुरैना के अलावा

मुरैना पुलिस की बड़ी सफलता, सीईआईआर पोर्टल की मदद से 401 गुप्त मोबाइल बरामद



ग्वालियर, धौलपुर, आगरा, गुना, शिवपुरी व अन्य क्षेत्रों से इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद

किया गया। बरामद किए गए मोबाइलों को मुरैना पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनके वास्तविक धारकों को विधिवत सत्यापन के बाद वापस सौंपा गया। अपनी खोई हुई संपत्ति वापस मिलने पर छात्र-छात्राओं, मजदूरों, किसानों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और गृहणियों सहित विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पुलिस महानिदेशक और मुरैना पुलिस के प्रति गहरा आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

पुलिस ने जुए के फंड पर मारा छापा, पांच जुआरी गिरफ्तार

मुरैना। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देश पर जिले में जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए के फंड पर छापा मारकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 21,000 नकद और ताश की एक गद्दी

जब्त की गई। पुलिस के अनुसार 10 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के सांकरा चौराहे के पास एक खेत में बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और पुलिस टीम के साथ मौके पर

पहुँचकर घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान जुआ खेल रहे पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 399/26 के तहत जुआ एक्ट की धारा 13 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पंकज यादव सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान



समय जगत, लटेरी। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम यातायात व्यवस्था सुधारने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लटेरी आरौ वादी के पास में समन चेकिंग अभियान चलाया, प्रभारी महोदय एवं थाना स्टाफ द्वारा शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों के पालन में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट

नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। वाहन चालकों के दौरान कुल 24 चालान बनाए गए। चालानों से समन शुल्क 7600 रु. प्राप्त किया गया। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट एवं अन्य यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

